मेहनतकशों का पैग़ाम मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

साप्ताहिक

Email : mazdoormorcha1987@gmail.com
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

जींद में जाट हारे	3
31 हजार करोड़ का घोटाला	4
एफआईआर से भड़के जेटली	5
दिव्यता का अंधेरा	6
ब्लैकमेल के शिकार बैंककर्मी	8

वर्ष 34 अंक -12 फ़रीदाबाद 3-9 फ़रवरी 2019 फोन - 9999595632 ₹ 2.50

नीलम-प्रबोध की यारी डीएवी मैनेजमेंट पर पड़ी भारी

पैनल द्वारा अयोग्य घोषित होने पर इन्टरव्यू किया रद्द

फ़रीदाबाद (म.मो.) एआईसीटीई (ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन) द्वारा कड़ी फटकार एवं कॉलेज को बंद करा देने की धमकी के चलते डीएवी कॉलेज मैनेजिंग कमेटी को प्रिंसिपल पद के लिये इन्टरव्यू का आयोजन करना पड़ा। हालांकि, चहेती नीलम के लिए इन्टरव्यू रद्द भी हुआ।

विदित है कि एनआईटी-3 स्थित डीएवी इन्स्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के प्रिंसिपल का पद बीते करीब आठ साल से खाली पड़ा है। खाली पड़े इस पद पर जिस नीलम गुलाटी को मैनेजमेंट द्वारा बैठा दिया गया, वह किसी भी तरह इस पद के लायक नहीं थी। लायक तो वह इस कॉलेज में सहायक प्रोफेसर बनने के भी नहीं थी। लेकिन मैनेजमेंट में बैठे प्रबोध महाजन ने उन्हें फीस क्लर्क से पहले प्रोफेसर और फिर प्रिंसिपल के पद पर बैठा दिया।

एआईसीटीई, जिससे मंजूरी पाकर ही इस तरह के कॉलेजों को चलाया जाता है, के नियमानुसार इस तरह के कॉलेजों में पढ़ाने वाले प्रोफेसरों व प्रिंसिपल की स्वीकृति संबंधित यूनिवर्सिटी से लेनी अनिवार्य होती है। उक्त कॉलेज के लिये यह स्वीकृति एमडीयू रोहतक से ली जानी थी। इसे पाने के लिए अभ्यार्थी को प्रथम श्रेणी में मास्टर्स डिग्री प्राप्त करनी होती है। नीलम गुलाटी के पास यह योग्यता न होने के बावजूद उन्हें जुगाड़बाजी से इन पदों पर बैठा दिया गया।

एआईसीटीई की धमकी के दबाव में डीएवी वालो को प्रिंसिपल पद के लिये

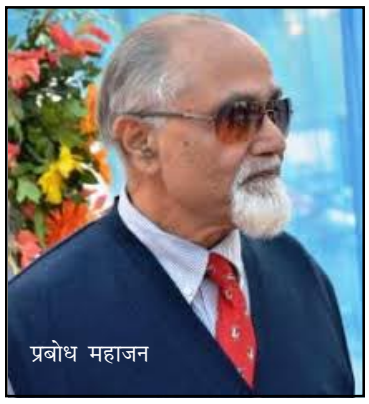

अखबारों में विज्ञापन निकलवाने पड़े। इन्टरव्यू पैनल में यूनिवर्सिटी का एक नुमायंदा होना जरूरी होता है जिस पर प्रबोध महाजन वीसी की ओर से दबाव डलवाते तो कोई भी नुमायंदा पैनल मे आने को तैयार नहीं होता था। कम से कम दो बार तो अवश्य ऐसे पैनेलिस्टों ने जब दबाव मानने से इंकार कर दिया तो इन्टरव्यू नहीं हो पाया।

इस बार 31 जनवरी को चित्रगुप्त मार्ग दिल्ली स्थित डीएवी कार्यालय में इन्टरव्यू पैनल आ बैठा। इसमें यूनिवर्सिटी की ओर से डा. राजकुमार विषय विशेषज्ञ और प्रोफेसर प्रदीप अहलावत, दोनों आईएमएसएआर, रोहतक के प्रोफेसर हैं। इनके अलावा प्रोफेसर हांडा आईटीएम फरीदाबाद तथा श्रीमती विमला एमडीयू रोहतक की प्रोफेसर हैं। पैनल ने इन्टरव्यू शुरू करने से पहले सभी उम्मीदवारों के दस्तावेज चैक किये तो नीलम गुलाटी को उन्होंने इस इन्टरव्यू में शामिल करने के लिए अयोग्य पाया।

जुगाड़बाजी द्वारा बनाये गये दस्तावेजों के आधार पर भी नीलम का तेरह वर्ष पढ़ाने का अनुभव नहीं बनता क्योंकि इनकी एमबीए की डिग्री ही 2010 की है। इस हिसाब से उनका नकली अनुभव भी मात्र आठ साल का ही बनता है। इस आधार पर पैनल ने सर्वसम्मति से नीलम को इन्टरव्यू में आने से रोक दिया। प्रबोध महाजन ने बहुत हंगामा किया कि इन्टरव्यू तो ले लो फिर चाहे फेल कर देना, लेकिन पैनल ने साफ कह दिया कि उनकी योग्यता इन्टरव्यू में पेश होने लायक भी नहीं है। इस पर झुंझलाये प्रबोध महाजन ने अपनी हेंकड़ी दिखाते हुए अन्य योग्य उम्मीदवारों का भी इन्टरव्यू नहीं होने दिया। सभी यह कहते हुए भगा दिया कि कोई भी उम्मीदवार पात्र नहीं है।

पैनल के इस आंकलन से यह बात स्पष्ट हो गयी कि नीलम केवल 2010 के बाद से ही बतौर प्रोफेसर पढ़ाने के लायक थी न कि 2001 से। इसका अर्थ यह हुआ कि डीएवी संस्थान ने योग्यता न होते हुए भी प्रोफेसर व बाद में प्रिंसिपल के पद पर बैठा कर 17 वर्ष तक एक अयोग्य पर मेहरबानी करके बतौर वेतन आदि करोड़ों रुपये संस्थान के बर्बाद कर दिये। इसके लिए डीएवी प्रबंधन में बैठे धर्म की दुकान चलाने वाले चोर तो जिम्मेदार हैं ही साथ में एमडीयू तथा एआईसीटीई के वे भ्रष्ट अधिकारी भी जिम्मेदार हैं जिन्होंने मोटी रिश्वतें खाकर इस गोरखधंधे को चलने दिया।

अब देखने वाली बात यह है कि बिना प्रिंसिपल के चल रहे इस डीएवी इंस्टीटयूट ऑफ मैनेजमेंट को एआईसीटीई तथा हरियाणा सरकार कब तक इसी तरह घिसटने देते हैं।

आरएसएस का चहेता बना डायरेक्टर सीबीआई : मध्यप्रदेश काडर के 1983 बैच के आईपीएस अधिकारी आरके शुक्ला को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली नियुक्ति कमेटी ने दो फरवरी को दो वर्ष के लिए सीबीआई चीफ नियुक्त किया है। कमेटी के अन्य सदस्य थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई और नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे।

योगेंद्र यादव : बजट में किसानों के वोट का सौदा किया है मोदी सरकार ने

जनज्वार। बजट में किसानों को प्रतिदिन 17 रुपए पर घिरी मोदी सरकार, किसी ने कहा के इतने की तो किसान बीड़ी पी जाता है दिनभर में तो किसान नेता योगेंद्र यादव के अनुसार यह राहत 5 सदस्य वाले परिवार के लिए प्रतिदिन रु3.3 है।

मोदी सरकार ने बजट में अनेक घोषणाएं कीं, जिनको चुनावी मौसम की घोषणाएं कहा जाने लगा है। इनमें से एक घोषणा प्रतिमाह किसानों को 500 रुपए देने की भी है, जिसको लेकर मोदी की खूब खिंचाई भी की जाने लगी है।

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसानों को 500 रुपए की राहत पर ट्वीट किया है, 'प्रिय नरेंद्र मोदी जी, आपकी पांच वर्षों की अक्षमता और अहंकार ने हमारे किसानों के जीवन को बर्बाद कर दिया। उनको प्रतिदिन 17 रुपये देना हर उस चीज का अपमान है जिसके लिए किसान खड़े हैं और काम कर रहे हैं।'

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि यह बजट खोदा पहाड़ निकली चुहिया की तरह है, खासकर किसानों के मामले में। किसानों को 6 हजार सालाना देने का ऐलान किया गया, लेकिन डीजल की कीमत बढ़ाकर, खाद, बीज, कीटनाशक की कीमत बढ़ाकर, सामानों पर जीएसटी लगाकर बोझ डाल रखा है। अगर किसान के एक परिवार में 5 लोग हैं तो एक के हाथ में 3 रुपया से भी कम आएगा, यानी आधा कप चाय भी नहीं आएगी। आधा कप चाय की कीमत देकर अगर वे अपनी पीठ थपथपा रहे हैं तो इससे

बड़ा मजाक और कुछ नहीं हो सकता।'

वहीं स्वराज पार्टी के अध्यक्ष और किसान नेता योगेंद्र यादव ने ट्वीट किया, 'सवाल था कि किसानों की आय दुगुनी का वादा करने वाली सरकार ने अब तक कितनी आय बढ़ाई है? लेकिन जवाब देने की बजाए ये तो किसानों के वोट का सौदा करने लग गए! असल में रु 6000 प्रति वर्ष का मतलब 5 सदस्य वाले परिवार के लिए प्रतिदिन रु 3.3 है। इससे तो एक कप चाय भी नही मिलती, चाय पर चर्चा के लिए!'

पत्रकार मानक गुप्ता लिखते हैं, "किसान को एक दिन के 17 रुपए दिए हैं, 18 की तो वो रोज़ बीड़ी पी जाता है" स्टूडियो में आए एक किसान नेता चेहरे पर बिना किसी भाव के बोले और मेरे रिऐक्शन का इंतज़ार करने लगे। हँसी कैसे रोकी है, मैं ही जानता हूँ।'

गौरतलब है कि केंद्र सरकार की किसानों को राहत योजना के तहत हर साल 6,000 रुपये की सहायता प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिये उनके बैंक खाते में प्रदान की जाएगी। यह राशि उन्हें 2,000-2,000 रुपये की तीन किस्तों में दी जाएगी। इस योजना का लाभ सिर्फ दो हेक्टेयर से कम जोत वाले किसानों को मिलेगा।

वेद समान मोदी स्वयं प्रमाण हैं?

रोजगार पर बजट में एक शब्द भी नहीं

बजट अनुसार अब तक मोदी जी ने 15 करोड़ 56 लाख मुद्रा लोन बंटवाये हैं।

मोदी जी का कहना है कि मुद्रा लोन लेने वाले स्वाभिमानी होते हैं, रोज़गार मांगते नहीं, रोज़गार देते हैं, और मोदी जी तो सच के सिवा कभी कुछ बोलते नहीं! इसलिए उनकी बात को पूरा सच मानकर ही हिसाब लगाते हैं.

मुद्रा लोन लेने वाले खुद तो रोज़गार से लगे ही हैं, इसलिए साढ़े 15 करोड़ रोज़गार तो यही हो गए!

अगर इनमें से हरेक ने औसत सिर्फ एक व्यक्ति को ही रोज़गार दिया हो तो साढ़े 15 करोड़ वो भी हुए, अर्थात कुल मिलाकर 31 करोड़ रोज़गार सिर्फ मुद्रा लोन से ही सृजित हुए जबकि मोदी जी ने सिर्फ 2 करोड़ रोज़गार का वादा किया था!

पर जब सरकार के लेबर ब्यूरो और NOSSO वाले सर्वेक्षण करने गए तो उन्हें इन 31 करोड़ में से कोई मिला ही नहीं, इसलिए बेरोज़गारी का आंकड़ा बढ़ गया!

अब मोदी जी के नीति आयोग से लेकर वित्त मंत्रालय वाले सारे प्रतिभाशाली "विशेष-अज्ञ" कह रहे हैं कि ...."ये तो पक्की बात है कि इतने रोज़गार सृजित हुए हैं."

पर इसका प्रमाण क्या है? क्योंकि मोदी जी ने ऐसा ही कहा है और मोदी जी ने कहा है तो वह सोलह आने सच है, क्योंकि मोदी जी की बात तो झूठ हो ही नहीं सकती! पर हमें और हमारे लेबर ब्यूरो तथा NSSO को पूरे दो साल हो गए इन्हें ढूंढते हुए, इनमें से कोई भी रोज़गाररत व्यक्ति ढूँढे से मिल नहीं रहा क्योंकि ये सब वैदिक विज्ञान और तकनीक सीख कर चंद्रमा पर चले गए हैं!

अब मोदी जी 2022 तक चंद्रमा पर गगनयान भेजने वाले हैं. यह यान जरूर इन मुद्रा लोन वाले रोज़गाररत व्यक्तियों को ढूंढ निकालेगा. अत: अब 2022 में ही रोज़गार का सही आंकड़ा जारी हो पाएगा!

2022 में रोज़गार का सही आंकड़ा चाहिए तो मोदी जी को ही वोट देकर दोबारा प्रधानमंत्री बनाना आवश्यक है!

- मुकेश असीम